जबलपुर | शनिवार | 2 अगस्त 2025 | वर्ष 76 | अंक 179 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

77 वां वर्ष संस्करण

5 अमेरिका के आगे झुक रही सरकार : कांग्रेस

6 व्यवधान के बिना बहस होना उचित

7 भारत में जापानी बैंकों का बढ़ रहा निवेश

8 खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच

एक नजर में

लेफ्टिनेंट जनरल सिंह बने सेना उप प्रमुख

नयी दिल्ली. लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यहां सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया. इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एवं स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के पद पर थे. कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर मातृ भूमि के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जनरल ऑफिसर को दिसंबर 1987 में पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) की चौथी बटालियन में कमीशन दिया गया था. वह ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं.

वाइस एडमिरल वात्सायन बने नौसेना उप प्रमुख

नयी दिल्ली. वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने शुक्रवार को यहां नौसेना के 47 वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया. इससे पहले वाइस एडमिरल ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के 71 वें कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को एक जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था. वह गनरी और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं.

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सूची जारी

पटना. चुनाव आयोग ने लगभग एक माह तक चले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आज बिहार में प्रारूप मतदाता सूची को जारी कर दिया है. चुनाव आयोग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों से इस संबंध में दावे और आपत्तियों को दर्ज कराने को कहा गया है. एक अगस्त से एक सितंबर 2025 तक संबंधित इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के समक्ष योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराया जा सकता है. बिहार के 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने एन्युमरेशन फॉर्म भरा है और सभी मतदाता सूची में शामिल है. आयोग ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व भागीदारी है. आयोग के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची से बिना कारण बताए कोई नाम नहीं हटाया जाएगा. बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के पहले चरण की जारी सूची को ऑनलाइन पोर्टल https://voters. eci. gov.in/download-eroll?stateCode=S®4 पर उपलब्ध कराया गया है.

गुस्ताखी माफ

भारत का कूटनीतिक दबाव

ट्रंप ने एक सप्ताह के लिए टाला टैरिफ

नई दिल्ली/वॉशिंगटन. अमेरिका द्वारा भारत पर प्रस्तावित 25 प्रतिशत टैरिफ को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है जो भारत की एक अहम कूटनीतिक जीत मानी जा रही है. 1 अगस्त से लागू होने वाले इस टैरिफ को अब 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, इस स्थगन के पीछे भारत द्वारा अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ-35 की डील को लेकर रखे गए रुख को एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालहि में 92 देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान और सीरिया प्रमुख रूप से शामिल हैं. भारत पर 25 फीसदी, पाकिस्तान पर 19 फीसदी, जबकि सबसे अधिक 41 फीसदी टैरिफ सीरिया पर लगाया गया. हैरानी की बात यह है कि चीन इस सूची से बाहर रखा गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूस और चीन से ऊर्जा व रक्षा संबंधी व्यापार को कारण बताते हुए टैरिफ को उचित ठहराया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, यह रुख वैश्विक युद्ध-विराम की उम्मीदों पर पानी फेरता है.

> **जवाब देने का अधिकार भी व्हाइट हाउस को ही होना चाहिए : रणधीर**
>
> नयी दिल्ली,1 अगस्त. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर संयमित लेकिन सशक्त जवाब दिया है. उन्होंने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा. रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी टैरिफ और व्हाइट हाउस की ओर से आए बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां तक टैरिफ का सवाल है, सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है. और जहां तक व्हाइट हाउस के बयानों की बात है, उस पर जवाब देने का अधिकार भी व्हाइट हाउस को ही होना चाहिए.

एफ-35 की जरूरत नहीं

अमेरिका के प्रस्ताव के तहत भारत को एफ-35 फाइटर जेट्स की बिक्री की पेशकश की गई थी, लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया की शर्तों पर जोर देते हुए इस डील पर सहमति नहीं दी. भारत के इस रवैये को अमेरिका के टैरिफ निर्णय के पीछे की मुख्य वजह बताया जा रहा है. सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है. मंत्री ने यह टिप्पणी तब की जब फरवरी में, भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफ-35) और अंडरसी सिस्टम जारी करने की अपनी नीति की समीक्षा करेगा. यह बयान सांसद बलवंत बसवंत वानखड़े के उस सवाल के उत्तर में आया है जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या भारत को एफ-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के संबंध में अमेरिका से कोई आधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था क्या.

एफ-35 फाइटर जेट प्रमुख विशेषताएं

- **स्टेल्थ तकनीक** : रडार में नहीं आता, दुश्मन की नज़रों से ओझल.
- **रफ्तार** : 1.6 मैक (लगभग 1930 किमी/घंटा)
- **अभियान क्षमता** : एक बार उड़ान भरने पर 2,200 किमी तक की रेंज
- **हथियार** : 25 मिमी गन, एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें
- **पायलट हेलमेट सिस्टम** : 360 डिग्री व्यू, नाइट विजन और एचयूडी डिस्प्ले एफ-35 के तीन वेरिएंट
- 1. **एफ-35ए** : पारंपरिक टेकऑफ/लैंडिंग (वायुसेना के लिए)
- **कीमत** : लगभग 8 करोड़ डॉलर
- 2. **एफ-35बी** : वर्टिकल टेकऑफ और शॉर्ट लैंडिंग (मरीन कोर के लिए)
- **कीमत** : करीब 10 करोड़ डॉलर
- 3. **एफ-35सी** : एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित (नौसेना के लिए)
- **कीमत** : 9 से 10 करोड़ डॉलर

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को

- **अधिसूचना सात अगस्त को होगी जारी**
- **21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नामांकन**

नयी दिल्ली, 01 अगस्त. उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को कराया जायेगा. इसके लिए अधिसूचना अगले सप्ताह गुरूवार को जारी की जायेगी. चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार, 7 अगस्त को जारी की जाएगी. इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

नामांकन पत्र गुरुवार, 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार 22 अगस्त को की जाएगी. नामांकन सोमवार, 25 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे.

आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, नौ सितंबर को पूर्वाह्न दस बजे से शाम पांच बजे तक कराये जायेंगे. मतगणना उसी दिन मतदान सम्पन्न होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में करायी जाएगी. सभी के मत का मूल्य एक समान (1) होगा. आयोग ने राज्य सभा के महासचिव प्रमोद चन्द्र मोदी को इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है.

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्य सभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोक सभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची पहले ही तैयार कर ली है जिसमें कुल 788 सदस्यों के नाम हैं. निर्वाचक मंडल में राज्य सभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य और लोक सभा के 543 सदस्यों के नाम हैं. राज्य सभा में इस समय पांच सीटें और लोक सभा में एक सीट रिक्त है.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जा रहा है.

दो हथियार तस्करी गिरोहों का भंडाफोड़

एक किशोर समेत चार को किया गिरफ्तार

अमृतसर 01 अगस्त. पंजाब में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले दो गिरोहों का भंडाफोड़ किया और एक किशोर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से हथियार बरामद करते थे. इन हथियारों का उद्देश्य गिरोहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और क्षेत्र में शांति भंग करना था.

यादव ने बताया कि आरोपियों के नाम सिकंदरजीत सिंह, निवासी गांव भगवानपुरा, तरनतारन, एक किशोर, निवासी गांव मस्तगढ़, तरनतारन, प्रदीप सिंह उर्फ बब्बी, निवासी अंतरजामी कॉलोनी, अमृतसर और जरनैल सिंह, निवासी न्यू शहीद उधम सिंह नगर, अमृतसर हैं. उनके पास से सात पिस्तौल, छह कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन और बी-डिवीज़न पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

> **समुद्र तट पर मिले थैले से 56 लाख के नशीले पदार्थ**
>
> रायगढ़, 01 अगस्त. महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को रायगढ़ जिले के मुरुड में काशीद बीच पर करीब 56 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 11 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों से भरे पैकेट जब्त किए. गौरतलब है कि काशीद बीच सफेद रेत, नीले पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाने वाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. पुलिस ने कहा, पैकेटों में 11 किलो 148 ग्राम चरस (हशीश) थी, जिसकी कीमत 55.74 लाख रुपये है. इस जब्ती से न केवल मुरुड तालुका में बल्कि पूरे कोंकण तट पर हड़कंप मच गया.

एनआईए ने बस्तर निवासी प्रियांशु को किया गिरफ्तार

जगदलपुर, 01 अगस्त. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र का रहने वाले युवक प्रियांशु कश्यप को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है.

प्रियांशु नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का हिस्सा था. प्रियांशु दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, नक्सलियों की नॉर्थ रीजनल ब्यूरो (एनआरबी) को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश में जुटा था. लंबे समय से एनआईए की रडार पर चल रहे प्रियांशु के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट, मेमोरी कार्ड और माओवादी दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा

सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की

नयी दिल्ली, 01 अगस्त. लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा करते हुए नारेबाजी की जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी.

पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने एक बार के स्थगन के बाद दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु की विपक्ष के सदस्य हाथों में नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आकर हंगामा करने लगे. हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाया और इसके बाद उन्होंने नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने मुद्दे सदन के पटल पर यह कहते हुए रखने को कहा कि उन्हें पढ़ा हुआ समझा जाएगा.

वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई. विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार न किए जाने पर उन्होंने जोरदार विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी. इसके चलते सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

अनिल अंबानी को ईडी का समन, 5 अगस्त को पेशी

नयी दिल्ली,1 अगस्त. रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होकर जवाब देना होगा. यह कार्रवाई पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत चल रही जांच के तहत की जा रही है. बताया जा रहा है कि अंबानी से बयान दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्यों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी. इससे पहले 24 जुलाई को अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जो तीन दिन तक चली.

प्रज्वल रेवन्ना को ठहराया दोषी

बेंगलुरु, 01 अगस्त. कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पूर्व घरेलू नौकरानी से जुड़े चर्चित दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया. अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया और अदालत आज सजा सुनाएगी.

कोर्ट का फैसला सुनने के बाद प्रज्वल भावुक होकर कोर्ट में ही फूट-फूटकर रोने लगे. कोर्ट से बाहर निकलते समय भी उनकी आंखों में आंसू थे. एफआईआर दर्ज होने के महज 14 महीने में यह फैसला सुनाया गया. टीम ने करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और जांच के दौरान कुल 123 सबूत इकट्ठा किए. केस की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी. इस मामले में 23 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.

इस मामले को लेकर जनता में व्यापक आक्रोश पैदा हो था और आरोप है कि रेवन्ना ने 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में अपनी नौकरानी के साथ बार-बार दुष्कर्म किया. पीड़िता ने दावा किया कि उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया.

संसद के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं

नयी दिल्ली, 01 अगस्त. उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अधिवक्ता योगमाया एम जी की इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. पीठ ने कहा याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता को सुझाव दिया कि वे कुछ महिला सांसदों को शामिल कर इस संबंध में एक निजी विधेयक पारित करने की दिशा में प्रयास करें. इस पर अधिवक्ता गुप्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कोई अधिनियम नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों को पोश अधिनियम के दायरे में लाने के लिए अदालत की व्याख्या चाहती हैं. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पोश अधिनियम के अर्थ में राजनीतिक दल कार्यस्थल और नियोक्ता माने जाएँगे, इसलिए उन्हें महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के प्रावधानों का पालन करना होगा. उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 2021 के एक फैसले का भी हवाला दिया.

15 हजार वेतन में 24 मकान

72 करोड़ का जाली दस्तावेज़ों के जरिए किया गबन | 30 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपति | 40 एकड़ कृषि भूमि व 4 लग्जरी गाड़ियां

बेंगलुरु. कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लोकायुक्त ने शुक्रवार को एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है.

कोप्पल जिले में कर्नाटक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (केआरआईडीएल) के पूर्व क्लर्क कलकप्पा निदागुंडी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है. महज 15,000 मासिक वेतन पाने वाले इस क्लर्क के पास 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि, 4 लग्जरी गाड़ियां, 350 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी पाई गई. यह संपत्ति न केवल उसके नाम, बल्कि उसकी पत्नी और भाई के नाम पर भी दर्ज है.

लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक, कलकप्पा और केआरआईडीएल के ही एक पूर्व इंजीनियर जेडएम चिंचोलकर पर आरोप है कि उन्होंने अधूरे प्रोजेक्ट्स के नाम पर जाली दस्तावेज़ों के जरिए करीब 72 करोड़ का गबन किया. लोकायुक्त विभाग ने शुक्रवार को छापा मारकर इन संपत्तियों की जांच शुरू की. इससे पहले मंगलवार को हासन, चित्रदुर्ग, चिक्कबलापुरा और बेंगलुरु में पाँच अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी हुई थी.

आरोप | मालेगांव बम विस्फोट के मुद्दे पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर भाजपा का तीखा प्रहार

भागवत को गिरफ्तार करने का बनाया था दबाव

नयी दिल्ली, 01 अगस्त. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मालेगांव बम विस्फोट के मुद्दे पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि गांधी परिवार के दबाव में तत्कालीन सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों से हिन्दू आतंकवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को कहा था.

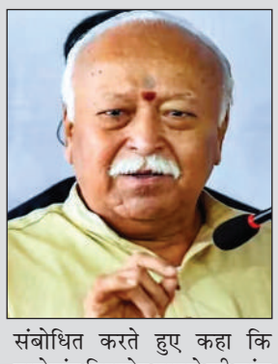

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले की जांच करने वाले आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भगवा आतंकवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाने और श्री भागवत को गिरफ्तार करने के लिए भारी दबाव डाला था. उन्होंने कहा कि श्री भागवत का नाम न तो आरोपत्र में था और न ही इस मामले में अन्य किसी जगह पर था. भाजपा नेता ने कहा कि संविधान का हवाला देते हुए मुजावर ने भागवत को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने कहा कि इसके बाद मुजावर पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ संगीन आरोप लगाये, जिसके कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गयी. बाद में उन्हें उन पर लगाये गये आरोपों से अदालत ने बरी कर दिया. पात्रा ने कहा, यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रतिशोधात्मक रवैये को दर्शाता है. यह सब गांधी परिवार के आदेश पर हो रहा था. भाजपा सांसद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अमेरिका जाकर उनकी जासूसी एजेंसियों से कहा कि भगवा आतंकवाद भारत के लिए सिमी से भी बड़ा खतरा है.

> अमेरिकी राजदूत से कांग्रेस के नेता ने कहा कि हिन्दू आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है. यह वोट बैंक की राजनीति के लिए गांधी परिवार का एजेंडा था. तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक सम्मेलन में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन कुछ साल पहले जब उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें अब भी लगता है कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना सही है तो शिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था.

भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के लिये पीएम मोदी ने दी सहमति

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिल रहा आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों के लिए उत्साहवर्धक है.

प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और धार में आरंभ होने वाले प्रधानमंत्री मित्र पार्क के भूमिपूजन में स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करने की मौखिक सहमति प्रदान की है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रदेश के किसान सम्मान कार्यक्रम में भी सहभागिता के लिए अनुरोध किया है. इन तीनों कार्यक्रमों के लिए शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तिथि निर्धारित की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया.